

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री नरहरी अमीन (गुजरात): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती रमिलाबेन बारा (गुजरात): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

Need for conversion of the sanctioned Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (F.I.D.F.) loan as grant for fishing harbours in the State of Andhra Pradesh

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI (Andhra Pradesh):* Sir, we have requested the Central Government to convert the Fisheries and Aquaculture

*English translation of the original speech made in Telugu.

[Shri Venkataramana Rao Mopidevi]

Infrastructure Development Fund (FIDF) loan as total grant to the three sanctioned fishing harbours in Andhra Pradesh. After the bifurcation of United Andhra Pradesh, the residuary State of Andhra Pradesh is having deficit budget. Consequent to the COVID-19 crisis the financial condition of Andhra Pradesh has further worsened. As the State of Andhra Pradesh ranks second in the country in marine products export, the revenue generated from these exports is considerable. The estimate cost for these three Central Government sanctioned fishing harbours is 379 crore rupee for Nizampatnam Phase-II, 286 crore rupees for Machilipatnam Phase-II and 350 crore rupees for Uppada in East Godavari district. Central Government has allotted 150 crore rupees towards each project. Keeping in mind the financial condition of the State of Andhra Pradesh, the Central Government should consider allotting this amount as grant but not as loan." Thank you, Sir.

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD (Uttar Pradesh): Sir, I associate with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Good. He says that instead of giving loan under the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund, it should be given as a grant.

Disadvantages being faced by children belonging to economically backward families due to online classes in schools

SHRI AHMED PATEL (Gujarat): Sir, I thank you for giving me time. समापति जी, कोरोना महामारी की वजह से पिछले छह महीने से स्कूल्स बंद हैं, इसीलिए कई निजी और सार्वजनिक स्कूलों में इस समय online classes चल रही हैं। इसके साथ-साथ ज्यादातर मामलों में फीस वसूलने के लिए और इसको justify करने के लिए ये कक्षाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि कुछ students ऐसे हैं, जो आर्थिक तौर पर बहुत ही गरीब हैं, कमजोर हैं और पिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनके पास न तो PC है, न laptop है, न ही smartphone है। इन कमियों की वजह से उन्हें जिस तरह से online classes में हिस्सा लेना चाहिए, वे उस तरह से हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह से उनके माँ-बाप पर और स्वयं उन पर मानसिक और वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। ऐसे हालात में, खास तौर पर जब डिजिटल इंडिया को अमीर और गरीब के बीच डिजिटल विभाजन का कारण नहीं बनने देना चाहिए, ऐसा हो रहा है।

महोदय, मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि कुछ राज्यों में छात्रों ने online कक्षाओं के तनाव के कारण आत्महत्याएं भी कर ली हैं।

महोदय, 75वें नेशनल सर्वे के दौरान यह पता चला है कि केवल 24 प्रतिशत घरों में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है और इनमें से केवल 9 परसेंट छात्र ही इंटरनेट का उपयोग कर रहे